

अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाओं में बेरोजगारी

विकास बंसल

शिक्षित बेरोजगारी का तात्पर्य उस बेरोजगारी से लगाया जाता है कि जब शिक्षित व्यक्तियों को अपनी योग्यतानुसार कार्य नहीं मिलता है और बेरोजगार रहते हैं। शिक्षित श्रम की परिभाषा माध्यमिक और इससे ऊपर शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के रूप में की जाती है। शिक्षितों में बेरोजगारी दर समग्र जनसंख्या में विद्यमान दर के तीन गुने से भी अधिक है।

भारत में अनुसूचित जाति की महिलाओं ने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करायी है। शिक्षा के सभी स्तरों एवं पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के महिला-पुरुषों ने प्रवेश पा लिया है। राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ प्रादेशिक स्तर पर उनका शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनुसूचित जाति के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, धीरे-धीरे उनमें विकास हो रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सूचक एवं सशक्तिकरण का माध्यम उच्च शिक्षा है। शिक्षा आज के वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे देश में संख्या के हिसाब से उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों की संख्या बहुत कम है। ऐसा इस कारण है कि अनुसूचित पूरी तरह से शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हुए हैं। उच्च शिक्षा में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के संदर्भ में यह कमी काफी गम्भीर है। उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों की भागीदारी एवं रुझान बढ़ा है। सरकारी योजनाओं ने भी इनके विकास को गति प्रदान की है।